

आज

बेबाक

केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने एनबीए नेताओं को नसीहत दी है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विवादाम्यद बयानबाजी से बचें। वरना नई दिल्ली की तरह बिहार में भी कड़ बार फरमान जारी हो चुके हैं, जिसे वे एक कान से सुन कर दूसरे कान से निकालते रहे हैं। दरअसल हर राजनीतिक दल में ऐसे बयानबाजों का दस्ता होता है जो जुवानदराजी को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। भले ही उनकी बकलोली से पार्टी का बंगधार हो जाए। उनका मूल मंत्र है- हम नहीं सुधरेंगे।

खास खबर

डेवी अब्राहम्स देश विरोधी गतिविधियों में शामिल, इसी वजह से उनका वीजा रद्द किया गया

नई दिल्ली। ब्रिटिश सांसद और लेबर पार्टी की नेता डेवी अब्राहम्स का ई-वीजा उनके भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से रद्द किया गया था। सरकार के सूत्रों के मुताबिक, अब्राहम्स को पिछले साल 7 अक्टूबर को बिजनेस मीटिंग में शामिल होने के लिए ई-वीजा जारी किया गया था, जो अक्टूबर 2020 तक वैध था। लेकिन, देश विरोधी गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद सरकार ने वीजा रद्द कर दिया। सरकार के सूत्रों ने कहा, -किसी भी व्यक्ति को वीजा या ई-वीजा देना, उसे रद्द करना या उसका आवेदन निरस्त करना संबंधित देश का विशेषाधिकार होता है।

चुनावी गारंटी कार्ड के 10 वादों को पूरा करने के लिए एक्शन में केजरीवाल

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में तीसरी बार सत्ता संभालने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने गारंटी कार्ड को लेकर अधिकारियों की बैठक बुलाई है। 16 फरवरी को तीसरी बार दिल्ली की कमान संभालने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल ने अपने गारंटी कार्ड पर काम करना शुरू कर दिया। सोमवार (17 फरवरी) को केजरीवाल ने सबसे पहले कैबिनेट की बैठक की थी। इसके ठीक अगले दिन सीएम ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की और गारंटी कार्ड में किए गए वादों पर काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी करने से पहले अरविंद केजरीवाल ने गारंटी कार्ड जारी किया था। गारंटी कार्ड में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी से जुड़े 10 अति महत्वपूर्ण कार्यों को शामिल किया

नई दिल्ली।

राजधानी दिल्ली में तीसरी बार सत्ता संभालने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने गारंटी कार्ड को लेकर अधिकारियों की बैठक बुलाई है। 16 फरवरी को तीसरी बार दिल्ली की कमान संभालने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल ने अपने गारंटी कार्ड पर काम करना शुरू कर दिया। सोमवार (17 फरवरी) को केजरीवाल ने सबसे पहले कैबिनेट की बैठक की थी। इसके ठीक अगले दिन सीएम ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की और गारंटी कार्ड में किए गए वादों पर काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी करने से पहले अरविंद केजरीवाल ने गारंटी कार्ड जारी किया था। गारंटी कार्ड में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी से जुड़े 10 अति महत्वपूर्ण कार्यों को शामिल किया

गरमा-गरम

भारत दुनिया का 5 वां बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बना, ठेका व्यवस्था बढ़ाकर डिजिटल, प्रोडम ने उसे

...वाह मोदी जी मंदी की हालत में मैं भी आगे बढ़ रहे हो

5

बजट प्रबंधन कानून दोबारा लिखने की जरूरत -योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अहलुवालिया परियोजनाओं के लिये वैकल्पिक वित्त व्यवस्था पर कार्यशाला

पारम्परिक बजट निर्माण प्रक्रिया से हटकर नवाचारी विचारों पर काम करें

डॉ शिशिर उपाध्याय



आर्थिक परियोजनाओं में बजट की कमी को दूर करने के लिये निजी - सार्वजनिक भागीदारी का कानून बनाने पर भी विचार करना चाहिए। वे आज यहाँ स्थानीय मिट्टी हॉल में परियोजनाओं के लिये वैकल्पिक वित्त व्यवस्था विषय पर वित्त विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कार्यशाला को

अधोसंरचना परियोजनाओं में बजट की कमी को दूर करने के लिये निजी - सार्वजनिक भागीदारी का कानून बनाने पर भी विचार करना चाहिए। वे आज यहाँ स्थानीय मिट्टी हॉल में परियोजनाओं के लिये वैकल्पिक वित्त व्यवस्था विषय पर वित्त विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कार्यशाला को

संबोधित करते हुए कहा कि पूरे विश्व का आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। इसलिए वित्तीय संस्थाओं और वित्त की व्यवस्था करने वाली सरकारों को भी अपनी सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में महत्वाकांक्षी युवाओं का बड़ा समुदाय रहता है और उसकी महत्वाकांक्षाएँ पूरी करने के लिए ज्यादा बजट

संसाधनों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बदले हुए और लगातार बदल रहे भारत और भारतीय राज्यों के लिए वित्तीय व्यवस्थाएँ करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इसलिए बैंकों, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्रों को परिवर्तन के साथ स्वयं को अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए पारम्परिक बजट निर्माण की प्रक्रिया शेष पृष्ठ 5 पर

भारत दुनिया का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना

जीडीपी की सालाना ग्रोथ 5 प्रतिशत रहने का अनुमान

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू को भी चालू वित्त वर्ष (2019-20) में भारत की जीडीपी ग्रोथ 5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। यह 11 साल में सबसे कम होगी। 31 जनवरी को पेश आर्थिक सर्वेक्षण में भी 5वें ग्रोथ का अनुमान ही जारी किया गया था। सर्वे में कहा गया कि ग्लोबल ग्रोथ में कमजोरी की वजह से भारत भी प्रभावित हो रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर की टिकटों के चलते निवेश में कमी की वजह से भी चालू वित्त वर्ष में ग्रोथ घटी। गितनी गिरावट आनी थी आ चुकी है। सरकार ने 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर (355 लाख करोड़ रुपए) की इकोनॉमी तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया है।



करोड़ डॉलर (209 लाख करोड़ रुपए) के स्तर पर पहुंच गई। ब्रिटेन 2.83 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी के साथ छठे और फ्रांस 2.71 लाख करोड़ डॉलर के साथ 7वें नंबर पर रहा। 2018 में भारत 7वें नंबर पर था। ब्रिटेन की 5वीं और फ्रांस की छठी रैंक थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब पुरानी नीतियों की बजाय ओपन मार्केट इकोनॉमी में खुद को डेवलप कर रहा है। भारत में 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। उस वक्त इंडस्ट्री पर नियंत्रण कम किया गया। विदेशी व्यापार और निवेश में भी छूट दी गई और सरकारी कंपनियों का निजीकरण शुरू हुआ था। इन वजहों से भारत की आर्थिक विकास दर में तेजी आई। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के

मुताबिक भारत का सर्विस सेक्टर दुनिया के तेजी से बढ़ते सेक्टर में से एक है। देश की इकोनॉमी में इसका 60 प्रतिशत और रोजगार में 28वें योगदान है। मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अहम सेक्टर हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने यह नहीं बताया कि जीडीपी का शेष पृष्ठ 5 पर

अर्थव्यवस्था टॉप -3 में आना हमारा लक्ष्य: ठाकुर

नवप्रदेश संवाददाता



इंदौर। 70 साल के प्रयासों के बाद हमारा देश जहां अर्थव्यवस्था के मामले में सिर्फ 111वें नंबर तक ही पहुंच पाया था। वहीं मोदी सरकार के प्रयासों से अब देश 5वें नंबर पर पहुंच गया है। हमें दुनिया में पहली तीन अर्थव्यवस्था में देश को लाकर खड़ा करना है। यदि देश का युवा तान ले तो खुद के साथ देश की उन्नति और प्रगति के रास्ते भी खोल सकता है। यह बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को इंदौर में युवाओं को संबोधित करते हुए कही। वे यहां संस्था सार्थक द्वारा आयोजित रोजगार मेले दिशा 2020 में युवाओं से रूबरू हो रहे थे। ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने देश में रोजगार को बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में एमएसएमई सेक्टर के लिए जहां टैक्स प्रतिशत कम किया गया है। वहीं नए उद्योग भारत में लगे, नई कंपनी यहां आए, इसके प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की रणनीति का असर नजर भी आ रहा है। दुनियाभर की कंपनियां शेष पृष्ठ 5 पर

दे किशतों में राज्यों को मिलेगा जीएसटी का बकाया रुपया

जीएसटी को लेकर कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को उनके हक का जीएसटी का पैसा देती आई है। जो भी बकाया है वह दो किशतों में दे दिया जाएगा, इसका उल्लेख वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में भी किया था। रियल स्टेट सेक्टर का गति देने के लिए 25 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। टैक्स छूट को लेकर कहा कि मोदी सरकार ने इस बजट में पांच लाख रुपए तक की आमदनी में पूरी तरह से टूट दी है।

निर्भया: दोषियों के वकील एपी सिंह बोले- आप लिखकर रख लो, 3 तारीख को फांसी नहीं होगी

निर्भया के दोषियों का 41 दिन में तीसरा डेथ वॉरंट जारी, 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाने का आदेश

नई दिल्ली। निर्भया केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को चारों दोषियों के

लिए नया डेथ वॉरंट जारी किया। पिछले 41 दिनों में यह तीसरा डेथ वॉरंट है। इसमें चारों दोषियों को 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश है। हालांकि चार दोषियों में से एक के पास अभी दया याचिका और क्यूरेटिव पिटीशन का

विकल्प है। ये दोनों विकल्प खारिज होने के बाद भी दोषी नए सिरे से राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेज सकते हैं। दोषियों के खिलाफ एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में भी चल रहा है, जिस पर फैसला आने तक फांसी नहीं हो सकती।

जम्मू-कश्मीर दौरे पर आर्मी चीफ नरवणे, सेना से बोले- पाक की नापाक कोशिशों का दें करारा जवाब

इस दौरान जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है

जनरल नरवणे ने सेना से साफ तौर पर कहा है कि को पाकिस्तान की उकसाने वाली कार्रवाई का करारा जवाब दिया जाए

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे संघर्ष विराम के उल्लंघन के बीच आर्मी चीफ एमएम नरवणे नागरोटा में हैं। आर्मी चीफ वहां सुखा बंदोबस्त का जायजा लेने पहुंचे हैं। सेना के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें हालात की जानकारी देते साथ ही एलओसी पर आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की पाकिस्तान की कोशिशों के बारे में बताएंगे। सेना के सूत्रों ने बताया, सैन्य

कमांडर वहां पाकिस्तान के प्रयासों को बेअसर करने के लिए सेना द्वारा किए गए उपायों की भी समीक्षा करेंगे। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कमांडरों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर पाकिस्तानी सेना एलओसी पर उकसाने वाली कार्रवाई करे तो उसे करारा जवाब दिया जाए। उधर कश्मीर स्थित 15वीं कोर की रणनीतिक कमान के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल कंवल जीत सिंह डिल्लन ने बताया है कि पाक अधिकृत कश्मीर में टेरेस्ट्रि कैप पूरी तरह से भरे हुए हैं। पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन करने की आड़ में आतंकवादियों की शेष पृष्ठ 5 पर

नाकामयाबी

अमेरिकी थिंकटैंक के मुताबिक पाकिस्तान अगर ब्लैकलिस्ट न भी हुआ तो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना मुश्किल है

आतंक पर पैतरे फेल, पाक को नहीं बचा पाए मलयेशिया, तुर्की ?

क्या हाफिज से बचेगा पाकिस्तान ?

इससे पहले एफएटीएफ ने 19 पॉइंट पाकिस्तान को दिए थे। पिछली बार इसमें से सिर्फ तीन शर्तें ही पाकिस्तान पूरी कर पाया था। हाफिज सईद की सजा के बाद अमेरिका ने कहा है कि अभी पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ और काम करने की जरूरत है। ब्लैकलिस्ट इंस्टीट्यूट की मदीहा अफजल ने टवीट कर रहा है कि हाफिज पर कार्रवाई अहम है लेकिन ये देखना होगा कि पाकिस्तान सरकार उसकी अपील पर क्या कार्रवाई करती है।



आ रहे पाकिस्तान की उम्मीदें खत्म होती दिख रही हैं। दरअसल, सूत्रों ने बताया है कि एफएटीएफ के उपसमूह ने आतंकवाद की वित्तीय मदद रोकने में विफल रहने पर पाकिस्तान को 'ग्रे लिस्ट' में बने रहने देने की सिफारिश की है। हालांकि अंतिम निर्णय शुक्रवार को होगा। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने आतंकवाद की फंडिंग रोकने के कितने सबूत एफएटीएफ को दिए हैं, उस पर संदेह है। पाक की इकलौती उम्मीद मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद को हाल में दी गई 11 साल की सजा से ही है। सूत्रों की मानें तो

पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट होने पर उसकी माली हालत चौपट हो जाएगी। उसके खिलाफ कई तरह के वित्तीय प्रतिबंध लग सकते हैं

एफएटीएफ प्लेनरी की बैठक पेरिस में हो रही है। पाकिस्तान का मित्र चीन इस बार अध्यक्षता कर रहा है

पेरिस। आतंकवाद का पालन-पोषण करने वाले पाकिस्तान के सभी पैतरे फेल हो गए हैं। फाइनेंशल ऐक्शन टास्क फोर्स में अब तक बचते-बचाते

हाल ही में चीन एफएटीएफ का चेयरमैन बना है जो पाकिस्तान का हिमायती रहा है। हालांकि उसने भी इस्लामिक स्टेट, अल कायदा और इनसे जुड़े आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई को अहम मानक बनाया है। पिछली बैठक में चीन ने खुल कर पाकिस्तान का साथ दिया था। इस बार तुर्की भी पाकिस्तान के साथ है।

पाकिस्तान आगे भी ग्रे लिस्ट में बना रह सकता है। पाकिस्तान के लिए यह बड़ा झटका है क्योंकि अगर शेष पृष्ठ 5 पर

## कोरोना का तोड़, भारतीय कंपनी ने बनाई प्रिवेंशन वैक्सीन, 6 महीने में ह्यूमन ट्रायल

चीन के वुहान शहर से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस का तोड़ निकालने का काम वैश्विक स्तर पर जारी

पुणे(ए.)। चीन के वुहान शहर से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस का तोड़ निकालने का काम वैश्विक स्तर पर जारी है। इस बीच पुणे की सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना की रोकथाम के लिए एक वैक्सीन विकसित करने में सफलता



पाई है। संस्थान को यह कामयाबी अपने साझीदार कंपनी अमेरिकन

बायोटेकनॉलजी फर्म कोडाजेनिकस की मदद से हासिल हुई है। फिलहाल, यह वैक्सीन प्राथमिक क्लिनिकल टेस्ट के लिए तैयार है और 6 महीने बाद वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा।

बताया गया कि कोरोना के इलाज के लिए एसआईआई-कोडाजेनिकस द्वारा विकसित की गई संभावित वैक्सीन वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक सुरक्षाकवच बनाने में अपेक्षाकृत कम समय लेती है। एसआईआई

### चीन में कोरोना से 1868 लोगों की मौत

बता दें कि चीन में घातक कोरोना वायरस से मृतकों की संख्या 1,868 हो गई। अभी तक इसके कुल 72,436 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचसी) ने बताया कि 1,097 मरीज काफी गंभीर है और 11,741 मरीजों की हालत नाजुक बनी है। अभी तक कुल 12,552 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुटी दी जा चुकी है। हॉन्ग कॉन्ग में सोमवार तक इसके 60 मामलों की पुष्टि हो गई थी, जहां इससे एक व्यक्ति की जान जा चुकी है।

के मालिक और सीईओ अदल पूनावाला ने बताया कि इस वैक्सीन-वायरस का स्टैन मूल

कोरोना वायरस के ही समान है और यह एक मजबूत इम्यून रिसर्पोन्स जनरेट करता है। उन्होंने

### साल 2022 तक होगा तैयार

पूनावाला ने बताया कि ह्यूमन ट्रायल के बाद इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से अप्रुव कर की जरूरत होगी, जिसके बाद इसे कोरोना वायरस के तोड़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मानव शरीर पर वैक्सीन की स्टडी में भी एक साल लगनेगे। उन्होंने साल 2022 की शुरुआत में वैक्सीन के पूरी तरह से तैयार हो जाने की उम्मीद जताई। पूनावाला ने कहा कि इस वैक्सीन का विकास समकालीन दुनिया में वैश्विक महामारी का जवाब देने की भारत की क्षमता को भी दर्शाता है।

कहा कि यह वैक्सीन 6 महीने में ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयार हो जाएगी। इसके बाद यह भारत की

ऐसी पहली वैक्सीन हो जाएगी, जिसे इतनी तेजी से इस चरण तक लाने में सफलता हासिल हुई है।

## जिंदा कसाब से फेल हो गया था हिन्दू टेरर प्लान!

कसाब की कलाई पर कलावा, ID में समीर चौधरी नाम, 26/11 को हिंदू आतंकवाद बताना चाहता था लश्कर: पूर्व पुलिस कमिश्नर मारिया

पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की किताब में मुंबई हमले को लेकर सनसनीखेज खुलासे

नई दिल्ली(ए.)। 26 नवंबर, 2008 के मुंबई हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अजमल आमिर कसाब अगर मौके पर ही मारा जाता तो आज दुनिया इस घटना को शायद हिंदू आतंकवाद मान रही होती। 26/11 अटैक को अंजाम देने वाला पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने इसे भारत के ही हिंदुओं की ओर से किए गए आतंकवादी हमले का रूप देने की बेहद खतरनाक साजिश रची थी। इसके लिए कसाब की कलाई पर हिंदुओं का पवित्र धागा 'कलावा' बांधा गया और पहचान पत्र (आईडी) में बेंगलुरु निवासी बताते हुए समीर दिनेश चौधरी नाम दिया गया था।

'रोजे में रची गई हमले की साजिश'

इस साजिश में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की भी मिलीभगत थी। पांव तले जमीन खिसका देने वाले ये सारे सनसनीखेज खुलासे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी पुस्तक Let Me



पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर ने लिखा कि कसाब को पकड़ा यकीन था कि भारत में मस्जिदों पर ताले जड़ दिए गए हैं और यहां मुसलमानों को नजाम पढ़ने की इजाजत नहीं है। जब उसे फ्राइम ग्रांच के लॉक-अप में रखा गया तो उसे अजान की आवाज सुनाई देती थी। तब उसे लगता है कि यह सच नहीं, उसके दिमाग की उपज है। मारिया लिखते हैं, 'जब मुझे यह पता चला तो मैंने मंहाले (जांच अधिकारी रमेश मंहाले) को एक गाड़ी में भेटो सिनेमा के पास वाली मस्जिद ले जाने को कहा।' मारिया कहते हैं कि कसाब ने जब मस्जिद में नजाम पढ़ते लोगों को देखा तो दंग रह गया।

Say It Now (लेट में से इट नाउ)' में किए हैं। मारिया के मुताबिक, मुंबई हमले की साजिश 27 सितंबर, 2008 को रची गई थी। उस दिन रोजे का 27वां दिन था।

'केंद्रीय एजेंसियों ने लीक की थी कसाब की तस्वीर'

मारिया का कहना है कि कसाब की तस्वीर

### हिंदू आतंकवाद का रूप देने की थी साजिश

पूर्व पुलिस कमिश्नर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अगर लश्कर का प्लान सफल हो जाता तो सारे अखबार और टीवी चैनलों पर 'हिंदू आतंकवाद' की हडिंग ही दिखती। उन्होंने लिखा, 'तब अखबारों की हेडलाइंस चीख रही होती कि कैसे हिंदू आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया। अलबता बेंगलुरु में उसके (कसाब के) परिवार और पड़ोसियों के इंटरव्यू के लिए टीवी पत्रकारों की लाइन लग गई होती। लेकिन, साजिश पर पानी फिर गया और (फर्मा) बेंगलुरु निवासी समीर दिनेश चौधरी) हकीकत में पाकिस्तान के फ़ौदकोट का अजमल आमिर कसाब निकला।' मारिया की किताब आने से पहले भी खबरों में बताया जा चुका है कि मुंबई हमलों में शामिल आतंकवादियों के पास हैदराबाद के अरुणोदय कॉलेज के आईडी कार्ड्स थे।

### 'नमाज पढ़ते लोगों को देख दंग रह गया कसाब'

पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर ने लिखा कि कसाब को पकड़ा यकीन था कि भारत में मस्जिदों पर ताले जड़ दिए गए हैं और यहां मुसलमानों को नजाम पढ़ने की इजाजत नहीं है। जब उसे फ्राइम ग्रांच के लॉक-अप में रखा गया तो उसे अजान की आवाज सुनाई देती थी। तब उसे लगता है कि यह सच नहीं, उसके दिमाग की उपज है। मारिया लिखते हैं, 'जब मुझे यह पता चला तो मैंने मंहाले (जांच अधिकारी रमेश मंहाले) को एक गाड़ी में भेटो सिनेमा के पास वाली मस्जिद ले जाने को कहा।' मारिया कहते हैं कि कसाब ने जब मस्जिद में नजाम पढ़ते लोगों को देखा तो दंग रह गया।

मुंबई पुलिस ने नहीं केंद्रीय एजेंसियों ने लीक की थी। उनका कहना है कि मुंबई पुलिस ने तो कसाब की सुरक्षा को खतरे की आशंका में उसकी पहचान उजागर नहीं होने देने की कड़ी भरपूर कोशिश की। मारिया ने कहा कि वह कसाब से हर दिन पूछताछ करते थे। कुछ दिनों बाद कसाब उनके साथ सहज हो गया और उन्हें जनाब कहने लगा।

### 'लूट के लिए लश्कर से जुड़ा था कसाब'

मारिया ने अपनी किताब में दावा किया कि कसाब पहले लूट के मकसद से लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा, उसे जिहाद से कोई लेना-देना नहीं था। कसाब और उसका दोस्त गुलापर लाल खान लूट से अपनी गरीबी मिटाना चाहता था। दोनों साथ में हथियार रखना चाहते थे ताकि लोगों को डर-भयकाकर लूट सके। मारिया ने लेट में से इट नाउ में लिखा है कि कसाब को तीन राउंड की ट्रेनिंग के बाद सवाल लाख रुपये और परिवार से मिलने के लिए हथियार भर की छुट्टी दी गई थी। उसने रुपये बहन की शादी के लिए परिवार को दे दिए थे।

## चुनाव के बाद भी हनुमान जी की शरण में आप, हर महीने होगा सुंदर कांड का पाठ

आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने हर महीने सुंदर कांड कराने की जानकारी दी है

नई दिल्ली(ए.)। राजधानी दिल्ली में तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है। दिल्ली की



जनता ने जनादेश दिया और बहुमत के साथ आप एक बार फिर सत्ता पर काबिज है। विधानसभा चुनाव 2020 में इस बार कई मुद्दों पर लड़ा गया। लेकिन इनमें सबसे खास रहे हनुमान जी। इस बार चुनावों में बीजेपी और आप के

बीच हनुमान जी को लेकर खासी बहस हुई है। अब ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी हनुमान जी का आशीर्वाद बनाए रखना चाहती है। इसी कड़ी में आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने जानकारी दी है कि हर महीने के पहले मंगलवार को अलग-अलग इलाकों में सुंदर कांड का पाठ कराया जाएगा।

सौरभ भारद्वाज ने सुंदर कांड के लिए निमंत्रण पत्र छपवाए हैं। इस निमंत्रण संदेश में लिखा है, 'चिराग दिल्ली अपनी गाड़ी आप चिराग करते हुए कहा कि पहले हमें बयान का अर्थ समझने की जरूरत है। इंदुरीकर ने अपने कीर्तन के दौरान कथित तौर पर कहा था कि सम संख्या वाली तारीख पर यौन संबंध बनाने से बचे का जन्म होता है और विषम संख्या वाली तारीख पर यौन संबंध बनाने से बेटी पैदा होती है। कीर्तनकार के इस बयान पर स्वयंसेवी संस्था महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने पिछले हफ्ते इंदुरीकर के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रदेश सरकार से मांग की थी।

'किस दिन संबंध बनाने से होंगे बेटा-बेटी' बताने वाले कीर्तनकार पर केस नहीं करेगी महाराष्ट्र सरकार औरंगाबाद। महाराष्ट्र सरकार यौन संबंध बनाने की तारीखों के आधार पर शिशु के लिंग निर्धारण संबंधी बयान देने वाले मराठी कीर्तनकार निवृत्ति महाराज इंदुरीकर के खिलाफ केस दर्ज नहीं कराएगी। प्रदेश सरकार में मंत्री बच्चू कडू ने इसकी पुष्टि



करते हुए कहा कि पहले हमें बयान का अर्थ समझने की जरूरत है। इंदुरीकर ने अपने कीर्तन के दौरान कथित तौर पर कहा था कि सम संख्या वाली तारीख पर यौन संबंध बनाने से बेटी का जन्म होता है और विषम संख्या वाली तारीख पर यौन संबंध बनाने से बेटी पैदा होती है। कीर्तनकार के इस बयान पर स्वयंसेवी संस्था महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने पिछले हफ्ते इंदुरीकर के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रदेश सरकार से मांग की थी।

### अहमदाबाद में स्वागत की तैयारी

## नमस्ते ट्रंप से पुती शहर की दीवारें



नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के अहमदाबाद पहुंचने से पहले उनके स्वागत और सुरक्षा की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बीच अहमदाबाद की सड़कें नमस्ते ट्रंप पोस्टर और पेंटिंग से ढंकी गई हैं। बड़े बड़े बैनर के अलावा दीवारों को अमेरिका भारत और नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की पेंटिंग से रंग दिया गया है।

## यूपी बजट: धार्मिक स्थलों का योगी सरकार ने रखा खास ख्याल अयोध्या समेत 7 शहर बनेंगे 'स्मार्ट'

साल 2020-21 के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेश किया बजट, धार्मिक स्थलों पर विशेष ध्यान दिया गया

लखनऊ(ए.)। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2020-21 के लिए मंगलवार को 5,12,860.72 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बजट पेश करते हुए जानकारी दी कि बजट में धार्मिक स्थलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या समेत यूपी के सात शहरों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।

खन्ना ने कहा कि पर्यटन संवर्धन योजना के तहत मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा-बुंदवान और शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक



### विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 200 करोड़

वाराणसी में संस्कृति केन्द्र की स्थापना के लिए बजट में 180 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वॉटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है। बजट में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपये, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपये तथा गोरखपुर और अन्य शहरों की मेट्रो के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रस्तावित किए गए हैं।

अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। तुलसी स्मारक भवन के सुदृढीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं अयोध्या हवाई अड्डे के लिए 500 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

### शरद पवार की नाराजगी के बीच बोले सीएम उद्धव ठाकरे

## केन्द्र को नहीं देंगे भीमा कोरेगांव केस



नई दिल्ली(ए.)। यलगर परिषद केस एनआईए को सौंपे जाने के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तरफ से सार्वजनिक तौर नाखुशी जाहिर किए जाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ किया केन्द्र को यलगर केस दिया गया है, भीमा-कोरेगांव केस नहीं। उद्धव ने कहा- यलगर परिषद केस और भीमा-कोरेगांव केस दो अलग मामले हैं। भीमा-कोरेगांव केस दलित लोगों से जुड़ा हुआ है और इसकी जांच केन्द्र को नहीं सौंपी जाएगी। इसे केन्द्र के हवाले नहीं किया जाएगा। केन्द्र को यलगर परिषद केस दिया गया है। एनआरसी से न सिर्फ हिन्दू-मुस्लिम बलिक आदिवासी भी

प्रभावित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आगे कहा- अगर एनआरसी लागू किया जाता है तो यह सिर्फ हिन्दू और मुसलमानों को ही प्रभावित नहीं करेगा बलिक आदिवासी भी प्रभावित होंगे। केन्द्र ने एनआरसी को लेकर अब तक कोई चर्चा नहीं की है। एनपीआर जगणना है और मैं नहीं मानता हूँ कि इसके कोई प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह हर दस साल में होता है।

### नई चुनौती

राज्य में 10 लाख से ज्यादा युवकों को अपने साथ जोड़ने के मिशन पर निकलेंगे प्रशांत

## बिहार में तीसरे मोर्चे की तैयारी में प्रशांत किशोर

बता दें कि जेडीयू ने कुछ दिन पहले प्रशांत को पार्टी से निकाल दिया था



तैयार करेंगे। प्रशांत की इस तैयारी को राज्य में तीसरे मोर्चे के संकेत में रूप में भी देखा जा रहा है।

**लॉन्ग टर्म योजना का किया ऐलान:** राजधानी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व जेडीयू नेता और इंडियन पॉलिटिकल ऐक्शन कमिटी (I-PAC) के चीफ किशोर ने कहा कि वह यहां किसी

राजनीतिक दल बनाने की घोषणा करने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा, 'मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के नजरिए से बिहार में युवाओं की एक फेज खड़ी करना चाहता हूँ।' 'बात बिहार की' कार्यक्रम से युवाओं को जोड़ेंगे: किशोर ने कहा कि वह युवाओं के अपने से जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम शुरू

पीके ने दिया तीसरा मोर्चा बनाने के संकेत? प्रशांत ने सीधे तौर पर बिहार की राजनीति में एंट्री का ऐलान तो नहीं किया लेकिन ये संकेत तो जरूर दे दिया कि वह भविष्य में ऐसा जरूर कर सकते हैं। बिहार में इस साल नवंबर में चुनाव होंगे हैं। उससे पहले प्रशांत की 'बात बिहार की' कार्यक्रम के जरिए युवाओं को जोड़ने की मंशा को तीसरे मोर्चे की कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रशांत ने कहा कि वह बिहार के युवाओं को राजनीति सिखाएंगे और उन्हें आगे करेंगे। उन्होंने कहा, 'मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन पंचायत स्तर से युवाओं को चुनकर उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा।' उन्होंने दावा किया बिहार में उनके पास सवा लाख सक्रिय सदस्य हैं।

करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, '20 फरवरी से बात बिहार की नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ। राज्य के 8,800 पंचायतों में से लड़कों की एक टीम बनाने जा रहा हूँ। अभी तक हमारे साथ 2 लाख 93 हजार लड़के जुड़ चुके हैं। हमसे जुड़े लोगों में बीजेपी के भी लोग शामिल हैं। 20 मार्च तक हम राज्य के 10 लाख लड़कों को शामिल करने

की योजना है।' उन्होंने कहा कि बिहार के गांव-गांव से लड़कों को जोड़कर आगे बढ़ने की रणनीति है। हमारी योजना है कि राज्य में 10 हजार अच्छे मुखिया जीतकर आएँ।

**सीएम नीतीश पर कसा बड़ा तंज:** उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य के लोगों ने ही दूसरे राज्यों के लोगों को ट्विटर और

बिना नाम लिए मोदी, शाह पर बोला हमला

प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बिना नाम लिए हमला किया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि गुजरात के आदमी को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि बिहार का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। प्रशांत ने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए नीतीश कुमार की हाथ जोड़कर मांग वाली बात का भी जिक्र किया। उन्होंने इसी मसले को लेकर पीएम मोदी को भी घेरा।

फेसबुक चलाना सिखाया है। ऐसे में यह कहना है कि हम इंस्टाग्राम नहीं हैं, सही नहीं होगा।

■ **न्यूज गैलरी**

**मकान बनवाना है तो हर वर्गमीटर पर देना होगा 4 हजार रुपए ज्यादा**

**भोपाल।** रियल स्टेट सहित 400 इंस्टीट्यूट को बढ़ावा देने के लिए पंजीयन विभाग अब कंस्ट्रक्शन कास्ट (निर्माण लागत) बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन में राज्य स्तर पर यह दाम बढ़ाए जाएंगे। हालांकि खाली प्लॉट या खेती की जमीन खरीदने पर यह कास्ट लागू नहीं होगी। इससे मकान, दुकान, फ्लैट सहित अन्य की रजिस्ट्री महंगी होगी। दरअसल, कलेक्टर गाइडलाइन में राज्य सरकार ने जमीनों की कीमतें ही नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन कास्ट में भी 20 प्रतिशत की कमी कर दी थी। प्रदेशभर में जहां शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कास्ट 10 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर से घटकर 8000 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गई थी। अब इस रेट को बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर करने की तैयारी की जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो आरआरसी, कबेलू या टीनशेड का मकान खरीदने वालों को रजिस्ट्री कराना महंगा पड़ेगा। यह कास्ट शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ेंगे।

केंद्रीय मूल्यांकन समिति की बैठक में इसे मंजूरी मिलना लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि खाली प्लॉट या कृषि भूमि खरीदने वालों को कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ने का असर नहीं पड़ेगा। यही नहीं वर्ष 2020-21 की नई गाइडलाइन के लिए तय होने वाले उपबंधों में से कुछ में परिवर्तन करने की कवायद भी शुरू हो गई है। हालांकि महानिरक्षक पंजीयक से लेकर अन्य अधिकारी इस संबंध में कुछ भी बोलने तैयार नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग लेता है 17 हजार इसलिए गाइडलाइन में बढ़ाई जा रही है कास्ट - पंजीयन कार्यालय के सुत्रों की मांगें तो पीडब्ल्यूडी ने पंजीयन विभाग को जो कंस्ट्रक्शन कास्ट के रेट दिए हैं, वह 17 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर है, जबकि शहरी क्षेत्र की कलेक्टर गाइडलाइन में 8000 रुपये प्रति वर्गमीटर ही कंस्ट्रक्शन कास्ट है। इसे देखते हुए ही पंजीयन विभाग ने कास्ट बढ़ाने का निर्णय लिया है। हालांकि वह केवल 40 प्रतिशत रेट ही बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।

**गुफा मंदिर बना भोपाल का तीर्थ स्थल, महाशिवरात्रि पर लगेगा मेला**

भोपाल। लालघाटी स्थित गुफा मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर सुबह पूजा-अभिषेक और शाम को रुद्राभिषेक, महाआरती की जाएगी। यहां पहुंचने वाले दर्शनार्थियों को दिनभर भंडारा चलेगा। मंदिर परिसर में एक दिवसीय मेला का आयोजन होगा। जिसकी तैयारियां वृहद स्तर पर शुरू हो गई हैं। जिसमें पूजा-पाठ की सामग्री के साथ बच्चों, महिलाओं के लिए झूले आदि की व्यवस्था रहेगी। वैसे आम श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर दिनभर खुला रहता है। मंदिर में महाशिवरात्रि पर सुबह से मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो जाएगी। महत्व: गुफा मंदिर जो राजधानी का एक प्रकार से हिंदू धार्मिक का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां बारह महीने श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। मंदिर के महंत चंद्रमादास त्यागी महाराज के अनुसार मंदिर में श्रद्धालुओं को यहां भक्ति के साथ आनंद भी मिलता है। इस मंदिर की यश कीर्ति दूर-दूर तक फैली है। देशभर के सैकड़ों संत मंदिर से जुड़े हुए हैं। विशेष - पहाड़ी की कंदराओं में बनी गुफा में जलकुंड में शिवलिंग स्थापित है। यह स्थान इसलिए भी अद्वितीय है कि जमीन से करीब 100 फीट की ऊंचाई पर पत्थरों पर कुंड बना है, जिसमें झरने से पानी बहता है। यह कुंड कभी सूखता नहीं है। हर समय पहाड़ी पर ठंडक बनी रहती है।

# सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला राहतकारी और स्वागतयोग्य

## महिलाओं को अवसर से वंचित करने के लिए, उन्हें कमजोर बताने वाली, संघी-भाजपाई सोच घृणित और शर्मनाक

**गुरु गोलवलकर से लेकर मोहन भागवत तक दशकों पुरानी है, संघ और भाजपा की महिला विरोधी घृणित सोच: शोभा ओझा**

**नवप्रदेश संवाददाता**

**भोपाल।** मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग की अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा ने आज जारी अपने वक्तव्य में कहा कि सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने संबंधी अपने ऐतिहासिक और स्वागतयोग्य फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को जो कड़ी फटकार लगाई है, उससे भाजपा व संघ का महिला विरोधी, भेदभावपूर्ण, घृणित चेहरा पूरी तरह से उजागर हो गया है।

आज जारी अपने वक्तव्य में उपरोक्त विचार व्यक्त करते हुए श्रीमती ओझा ने कहा कि देश की आधी आबादी के पक्ष में दिये गये अपने ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि “सामाजिक व मानसिक कारण बताकर, महिला अधिकारियों को अवसर से वंचित करना न सिर्फ भेदभावपूर्ण है, बल्कि अस्वीकार्य और असंवैधानिक है, केन्द्र को अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए।” सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चन्द्रचूड़ व जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ द्वारा सरकार को तीन माह के भीतर ही, आदेशों का पालन सुनिश्चित करवाने की बात कहना भी, मोदी सरकार की महिला विरोधी सोच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के

आश्चर्यजनक नहीं हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संघ के सर्वाधिक पूज्य सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर से लेकर वर्तमान सरसंघ चालक मोहन भागवत तक, महिलाओं के प्रति संघ की सोच अब तक क्या रही है! ओझा ने कहा कि आज से दशकों पहले ही गुरु गोलवलकर ने महिलाओं के प्रति अपनी सोच को स्पष्ट करने हुए आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गनाइजर में 30 जनवरी 1966 के अंक में लिखा था कि “अब यह साफ होता जा रहा है कि महिलाओं को मताधिकार देने का फैसला गलत और फिजूल था, इतिहास गवाह है कि जहां कहीं महिलाओं ने हुकूमत की है, वहां

अपराध, गैर-बराबरी और अराजकता इस तरह फैली है, जिसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता।” अपने उसी दुस्साहसी लेख में उन्होंने यहां तक लिख दिया था कि “महिला अगर विधवा हो और शासक हो जाए तो मुल्क की बदनसीबी शुरू हो जाती है।” ओझा ने कहा कि गुरु गोलवलकर के उक्त महिला विरोधी विचार आज भी संघ और भाजपा की सोच पर हावी हैं, गुरु गोलवलकर के निधन के दशकों बाद वर्तमान सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भी अपनी निम्नस्तरीय सोच को उजागर करते हुए अपने एक भाषण में कहा है कि “जिसे आप विवाह संस्कार समझते हैं, दरअसल वह एक सौदा है, पुरुष, महिला से यह कहता है

कि तुम मेरा घर संभालो, मैं तुम्हें भोजन व सुरक्षा दूंगा, इसलिए महिला से पुरुष का अधिकार ज्यादा है, जब तक महिला सौदे की शर्तों का पालन करती है, तब तक ठीक है, अन्यथा उसे छोड़ दो।” अपने बयान के अंत में श्रीमती ओझा ने कहा कि केवल उक्त दो उदाहरणों से ही साफ है कि संघ प्रमुख या भाजपा अध्यक्ष पद पर आज तक किसी महिला को क्यों नियुक्त नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के बाद देश की आधी आबादी को दबाए रखने वाली, महिला विरोधी संघ और भाजपा की विचारधारा को लगा करारा झटका, महिलाओं के लिए सूकून के साथ ही शीतल हवा की सुखद बयार भी लेकर आया है।

## पति, पत्नी और 16 घंटे की नौकरी, मामला पहुंच गया तलाक तक

**नवप्रदेश संवाददाता**

**भोपाल।** शादी से पहले जो प्रोफेशन आकर्षण का केंद्र था, वह शादी के बाद जी का जंजाल बन गया। पति का प्रोफेशन ही रित्ते में अलगवाव का कारण बन गया। प्राइवेट कंपनी में जाँब कर रहे पति के 15 से 16 घंटे की नौकरी करने के कारण पत्नी ने पति से तलाक मांग लिया। मामला कुटुंब न्यायालय तक पहुंच गया, जहां कार्डसिलिंग में दोनों ने अपने-अपने तर्क रखे। पत्नी की शिकायत है कि पति के लिए नौकरी शकाल है। पति का ऑफिस से घर आने-जाने का कोई निश्चित समय नहीं है। घर से ऑफिस कभी भी बुला लिया जाता है। वहीं, पति का तर्क है कि जाँब के कारण वह मजबूर है। दोनों की शादी 2017



में हुई थी, लेकिन साथ में सिर्फ दो माह ही रहे। परेशान होकर पत्नी मायके चली गई। वह अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। ससुराल वाले पढ़ाई नहीं कराना चाहते : पत्नी ने कहा कि वह दिल्ली में रहकर नेट और यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है, लेकिन ससुराल वाले पढ़ने नहीं देना चाहते। पत्नी ने शर्त रखी है कि अगर वह ससुराल में

रहेगी तो यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग करेगी, जबकि पति इससे इंकार कर रहा है। पत्नी का कहना है कि पति के ऑफिस से आने-जाने का निश्चित कोई समय नहीं है। सुबह 10 बजे से ऑफिस गए तो रात के 12 से 2 बजे के बीच ही घर आते हैं। ऐसे में मेरे घर में रहने का पति के लिए कोई मतलब नहीं है। अगर पति सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो सुबह से शाम तक ऑफिस का समय रहेगा। पति ने कहा कि शादी के बाद पत्नी मेरे घर में सिर्फ दो माह तक रहें। इतने दिनों में घर का कोई काम नहीं किया। मेरे जाँब को लेकर हमेशा लड़ाई करती है, जबकि जाँब के बारे में शादी से पहले ही बता दिया था।

## सड़क हादसों को कंट्रोल करने के लिए हाईटेक हो रही मप्र पुलिस

**नवप्रदेश संवाददाता**

**भोपाल।** मध्य प्रदेश में सड़क हादसों को कंट्रोल करने के लिए अब पुलिस को हाईटेक संसाधनों से लैस किया जा रहा है। पुलिस विभाग ने अपने महकमे के लिए नए-नए उपकरण खरीदे हैं। इनमें से कुछ को जमीन पर पहुंचाया गया है और कुछ उपकरणों को दिया जाना अभी बाकी है। इन उपकरणों में बॉडी वॉन कैमरा, स्पीड रडार और साउंड मीटर शामिल हैं। पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान से मिली जानकारी के अनुसार रोड सेफ्टी क्रियान्वयन समिति की बैठक में इन उपकरणों को खरीदने का अनुमति दी गई थी। इनका इस्तेमाल पहले बड़े शहरों में किया जा रहा है। एआईजी प्रमोद शर्मा ने बताया कि स्पीड रडार गन ले रहे हैं, जिससे स्पीड पर कंट्रोल के साथ कार्रवाई भी आसानी से हो सकेगी। बीथ एनेलाइजर बांट दिए गए हैं। इसके अलावा 500 बॉडी वॉन कैमरे लिए गए हैं। जल्द ही इनमें से 220 ट्रैफिक पुलिस और बाकी



की थाना पुलिस को दिए जाएंगे। बॉडी वॉन कैमरों के जरिए पुलिस और वाहन चालक की हर एक गतिविधि कैद होगी और काम में पूरी तरह पारदर्शिता आएगी। साथ ही अभद्रता की घटना में कम होगी। ये हैं हाईटेक उपकरण

**1-डी वॉन कैमरा-** ट्रैफिक को संभालने के दौरान अवसर पुलिस पर अभद्रता, अवैध वस्तु की के आरोप लगते हैं। इन सबको रोकने और काम में पारदर्शिता लगाने के लिए बॉडी वॉन कैमरा का इस्तेमाल किया जाएगा।

**2-स्पीड रडार-** तेज गति से वाहन चलाने वालों पर शिकंजा

**भोपाल।** मध्यप्रदेश की राजधानी की सुरक्षा रात में कैसी है, और पुलिस यहां किस तरह से लगातार गश्त करती है। इसका जीता जाता उदाहरण उस समय मिला। जब करौंद क्षेत्र के दुकानदारों ने मॉलवार सुबह अपनी दुकानें खोलें। दुकान खोलने के साथ ही कई दुकानदारों के मुंह से चीख निकल गई। दरअसल दुकान खोलते ही दुकानदारों ने अपनी दुकानों से काफी माल गायब पाया। इसका कारण ढूढ़ने पर पता चला कि चोरी हुई सभी 6 दुकानों में रात के समय संधमारी की गई है। यानि बिना ताला तोड़े ही चोर दीवार में छेद कर माल ले उड़े, वहीं रात में गश्त का रोना रोने वाली पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं लगी दरअसल करौंद चौराहे पर ऐतिहासिक चोरी का मामला सामने आया है। चोरी में अब तक ये नहीं बताया जा सका है कि कुल कितने का माल चोर अपने साथ ले गए हैं। जानकारी के अनुसार इस चोरी की वारदात के दौरान चोरों ने केवल मोबाइल दुकानों को ही अपना टारगेट बनाया। इस घटना के चलते करौंद मोबाइल एसोसिएशन में नाराजगी व्याप्त है।

## थाईलैंड एम्बेसी ने जिला विधिक प्राधिकरण से कहा- एक देश, एक कानून, फिर मध्यप्रदेश में विदेशियों से भेदभाव क्यों?

**पत्र लिखकर कहा- देह व्यापार में पकड़ी गई युवतियों को माना जाए विविटम**

**प्राधिकरण बोला- इस संबंध में मुंबई और गोवा से जानकारी मंगाई गई है**

**नवप्रदेश संवाददाता**

**भोपाल।** देह व्यापार में पकड़ी गई युवतियों के पक्ष में थाईलैंड एम्बेसी खड़ी हो गई है। एम्बेसी के प्रतिनिधियों ने जिला विधिक प्राधिकरण पहुंचकर कहा कि एक देश, एक कानून होने के बावजूद थाईलैंड की युवतियों के साथ विविटम की जगह आरोपी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। एम्बेसी के प्रतिनिधियों ने कहा कि मुंबई और गोवा में देह व्यापार में पकड़ी गई युवतियों को विविटम माना जाता है। इस मामले में थाईलैंड एम्बेसी के प्रतिनिधियों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को एक पत्र देकर पकड़ी गई युवतियों की कानूनी मदद करने की बात की है। मामले में प्राधिकरण ने एम्बेसी के द्वारा दिए गए पत्र को नेशनल विधिक सेवा प्राधिकरण भेज दिया है। एम्बेसी के प्रतिनिधियों ने प्राधिकरण में कहा कि मुंबई और



गोवा में देह व्यापार में पकड़ी गई थाईलैंड की युवतियों को विविटम मानते हुए शेल्टर होम भेजा जाता है। उन्हें कानूनी सहायता दी जाती है, जबकि मप्र में उन्हें आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। जमानत लेने के बाद उन्हें शहर में शेल्टर लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्राधिकरण के सचिव आशुतोष मिश्रा ने बताया कि मामले में मुंबई और गोवा से जानकारी मंगाई गई है। साथ ही थाईलैंड एम्बेसी द्वारा दिए गए पत्र को नेशनल विधिक सेवा प्राधिकरण भेजा है। वहां से जो भी दिशा-निर्देश मिलेंगे, उस पर काम किया जाएगा। फिलहाल थाईलैंड की देह व्यापार में पकड़ी गई

महिलाओं को विधिक सहायता दी गई है। उनका कहना है कि यह देखा होगा कि वास्तव में पकड़ी गई युवतियां विविटम हैं भी या नहीं। पकड़ी गई सभी थाईलैंड की युवतियों का प्रकरण कोर्ट में विचारार्थ है। सचिव का कहना है कि वैसे कानून के हिसाब से पकड़ी गई वह युवती, जिसे जब्त करी बंधक बनाकर देह व्यापार कराया जा रहा है या फिर नाबालिग लड़की ही विविटम मानी जाती रही है। मुंबई और गोवा से जानकारी मंगाई गई है कि विदेशी महिला को कानून की किस धारा के तहत विविटम माना गया है। उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि मामले में क्या करना है।

## बयान स्वास्थ्य विभाग से काम करवाना भगवान को खुश करने जैसा: विदिशा कलेक्टर

**नवप्रदेश संवाददाता**

**भोपाल।** भोपाल संभाग के सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अफसरों की सोमवार को भोपाल कमिश्नर कल्पना श्रीवास्तव ने वीडियो कांफ्रेंस ली। इसमें अधिकारियों से वन-टू-वन चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा काफी गहराया रहा। संस्थागत प्रसव के आँकड़ों पर सवाल खड़े करते हुए तत्काल इसे दुरुस्त करने की बात कही गई। बैठक में विदिशा कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से जिले में काम कराना, भगवान को प्रसन्न करने जैसा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोई भी काम करने को कहा जाता है, वह उसको सुनता तक नहीं है। सीएमएचओ



से लेकर आला अधिकारी तक तबज्जो नहीं देते हैं। इससे नाराज संभागयुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य विभाग के

अधिकारी सुधीर जैसानी को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी दिए गए

आदेशों का पालन करें। डॉक्टर डे पर भ्रमण कर कलेक्टरों को सॉपे रिपोर्ट

भोपाल कमिश्नर ने निर्देश दिए कि मातृ वंदना योजना में विदिशा, रायसेन, भोपाल की स्थिति में अत्यधिक कार्य किए जाने की जरूरत है। सेक्टर डॉक्टरों के अनुसार इस क्षेत्र में भ्रमण कर वस्तु स्थिति रिपोर्ट कलेक्टरों को सॉपे, तभी सभी योजनाओं की स्थिति सामने आएगी। उन्होंने कहा कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रियाशील बनाया जाए साथ ही एएनएम का युक्तियुक्तकरण करें। लाडली लक्ष्मी योजना में सीओर को छोड़कर सभी जिलों को कार्य करने की जरूरत है। वन स्टॉप सेंटर एवं

आईसीपीएस में मापदंडों के अनुसार कार्य किया जाए। बैठक में एडीजीपी आदर्श कटियार और सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। गेहूं उपाजंन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए भोपाल कमिश्नर ने कहा कि इस बार गेहूं की बंपर पैदावार की संभावना है। इसको देखते हुए अधिक मात्रा में भंडारण की सभी व्यवस्थाएं भी 15 मार्च तक पूरी की जाएं।

**इन विभागों को दिए यह निर्देश**

माफिया मुक्त मध्यप्रदेश अभियान: हार्डसिंग सोसायटियों की धोखाधड़ी के शिकार नागरिकों को न्याय दिलाएं। सोसायटी के जिन सदस्यों को प्लॉट नहीं

मिले, उन्हें ब्याज सहित राशि वापस लौटाई जाए। माफिया अभियान में तेजी लाएं और सूदखोरों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करें।

**पुलिस व कानून व्यवस्था:** आगामी माह में होने वाले त्योहारों को देखते हुए उत्कृष्ट कानून व्यवस्था बनाए रखें तथा धरना-प्रदर्शन आदि आयोजित होने पर धैर्यपूर्वक और संवदेनात्मक रवैया अपनाना। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों के राहत प्रकरणों में त्वरित राहत राशि वितरण के लिए अनुविभाग स्तर पर प्रति सप्ताह एसडीओपी और एसडीएम की संयुक्त बैठक की जाए।

## संपादकीय

## कब सुलझेगा शाहीन बाग मसला

देश की राजधानी नई दिल्ली में नए नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले 15 दिसंबर से जारी शाहीन बाग प्रदर्शन का मसला आखिर कब सुलझेगा? पहले तो यह माना गया था कि नई दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद शाहीन बाग से प्रदर्शनकारी हट जाएंगे। किन्तु नई दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी यह प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शाहीन बाग प्रदर्शन के कारण नई दिल्ली के शाहीन बाग क्षेत्र में जो चक्काजाम की स्थिति बनी हुई है उस लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए 3 वार्ताकारों की नियुक्ति की है और इस मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी की निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी कानून के खिलाफ सभी को प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है लेकिन सड़कों को अवरुद्ध किया जाना चिंता का विषय है यदि लोग इसी तरह सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा। अब देखना होगा कि अपनी जिद पर अड़े शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त वार्ताकारों की बात मानते है या नहीं प्रदर्शनकारी गुहमंत्री से बातचीत करने के लिए उनके निवास तक रैली निकालने की कोशिश कर चुके है जिन्हे पुलिस ने वापस लाया दिया था। दरअसल प्रदर्शनकारी यह चाहते है कि केन्द्र सरकार के जिम्मेदार नुमाइंदे उनके साथ बातचीत करें। वे नए नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग पर ही अड़े हुए है जबकि देश की संसद ने यह कानून पारित कर दिया है इसके बाद भी प्रदर्शनकारी कुछ राजनीतिक दलों के बहकावों में आकर बेतुकी मांग पर अड़े हुए है। उन्हे इस बात की कतई कोई फिक्र नहीं है के दो माह से अधिक समय तक उन्होंने शाहीन बाग की मुख्य सड़क को बांश्चित कर लाखों लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। इस प्रदर्शन के चलते हजारों लोग लंबी दुरी तय कर अपने गंतव्य पर पहुंच पाते है। स्कूली छात्र छात्राओं और मरीजों को भी इस प्रदर्शन के चलते भारी दिक्कों का सामना करना पड़ रहा है। अब यह प्रदर्शन किसी भी कीमत पर खत्म होना ही चाहिए यदि प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए वार्ताकारों की बात नही मानते है तो सरकार को बल पूर्वक पूरी सख्ती के साथ इन प्रदर्शनकारियों को शाहीन बाग से हटा देना चाहिए।

## विचार मोर्चे पर महिलाएं

आखिरकार थलसेना में भी महिलाओं को बराबरी का हक मिल गया। उन्हें स्थायी कमीशन और कमांड पोस्टिंग दिए जाने का रास्ता खुल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक अहम फैसले में कहा कि उन सभी महिला अप्सरों को तीन महीने के अंदर आर्मी में स्थायी कमीशन दिया जाए, जो यह विकल्प चुनना चाहती हैं। इसके लिए मार्च 2019 के बाद सेना से जुड़ने की सरकारी शर्त भी अदालत ने हटा दी। अभी तक आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) के तहत 14 साल की सेवा दे चुके पुरुष सैनिकों को ही स्थायी कमीशन का विकल्प मिलता रहा है। महिला सैनिकों को इसके लिए हकदार नहीं माना जाता था। इसके विपरीत वायुसेना और नौसेना में महिला अप्सरों को स्थायी कमीशन मिलता रहा है। इस तरह इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के साल 2010 के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। महिला अप्सरों को स्थायी कमीशन देने की इजाजत दिल्ली हाईकोर्ट ने 2010 में दी थी, फिर 2 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी थी। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने इस पर अमल नहीं किया।

हाईकोर्ट के फैसले के नौ साल बाद फरवरी 2019 में सरकार ने सेना के 10 विभागों में महिला अप्सरों को स्थायी कमीशन देने की नीति बनाई, लेकिन साथ में यह शर्त भी जोड़ दी कि इसका फायदा मार्च 2019 के बाद से सर्विस में आने वाली महिला अप्सरों को ही मिलेगा। इस तरह वे महिलाएं स्थायी कमीशन पाने से वंचित रह गईं, जिन्होंने इस मसले पर लंबे अरसे तक कानूनी लड़ाई लड़ी थी।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दलील दी थी कि सेना में ज्यादातर जवान ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और महिला अधिकारियों से पैजैजी हुकम लेना उनके लिए सहज नहीं होगा। यह भी कि महिलाओं की शारीरिक स्थिति और पारिवारिक दायित्व जैसी बहुत सी बातें उन्हें कमांडिंग अप्सर बनाने में बाधक हैं। इस दलील को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को कमांड पोस्ट पर न खराना अलाफ़िक है और समानता के खिलाफ भी। केंद्र सरकार को महिलाओं के प्रति मानसिकता बदलनी होगी और सेना में समानता लानी होगी। कमांड पोस्टिंग का अर्थ है किसी यूनिट, कोर या कमान का नेतृत्व करने वाली पोस्टिंग। दरअसल, समाज की मानसिकता बदलने के साथ महिलाओं को सेना में शामिल तो कर लिया गया पर उन्हें लेकर सेना के नेतृत्व में झिझक मौजूद रही है जो अभी तक मिटी नहीं है। महिलाओं ने सेना के दरवाजे अपने लिए खुलने के बाद यह साबित किया है कि सारे काम वे पुरुषों जितनी ही कुशलता से कर सकती हैं। पैजैजी इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। उनकी अगली मंजिल कॉम्बैट रोल है। उन्हें इस भूमिका में लाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार और सेना पर छोड़ दिया है। उम्मीद करें कि महिलाएं जल्द ही इस भूमिका में भी नजर आएंगी।

### पाठकों की बात

#### जीवन में जब निराशा



जीवन में जब निराशा के बादल हमारे सामने हों तब समय और भाग्य पर निर्भर रहने से बेहतर होता है कि हम स्वयं अपने मार्ग बनाकर निरंतर आगे बढ़ें। हमारा मनोबल और हमारी सकारात्मक ऊर्जा ही हमें सफलता तक पहुँचाने में मुख्य भूमिका निभाती है।

- **सुनील शुक्ला**

#### कहे कलेण्डर प्यार से



कहे कलेण्डर प्यार से,अरे आदमी सीख । बदली है मैंने सदा, ..... रोजाना तारीख ॥ रोजाना तारीख, हकीकत कहता तुझको । किंतु एक तारीख, बदल देती है मुझको ॥ करना नही घमंड, .... मचाना नही बवंडर । बदलेगा दिनमान, एक दिन कहे कलेण्डर ॥

- **रमेश शर्मा,**

### पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

#### ख़ास पानी



चांद फलक पर, गगन देखता रहा । बहार फूलो पर , चमन देखता रहा । मचल मचल लहर चली नदी का मन देखता रहा । पंख जो पसार कर उड़ान पंछी भर रहे , शीतल बयार बन पवन देखता रहा । नवकण्ठोल खिल उठे शजर शजर सज गये , बसंत का राग बन , कुंज कुंज देखता रहा । डामगा नाव पर तान छेड़ा मल्लह ने , धूप किनारे पर खड़ा इंतजार , कोई देखता रहा । पहाड़ों पर फिसलती हुई , धूर जब उतर रही , बैचैन झरोखों का कपाट देखता रहा ॥ - **शिखा लाहीरी**

### ये जो भटकन है न!तुम तक जाने की

ये जो भटकन है न!तुम तक जाने की एक तलाश है एक दूसरे को जानने की गुमशुदा सी हूं तुम बिन तुझ में खुद का ढूंढ रही हूँ सदियों से भटकते हुए लम्हे की तरह भटक रही हूँ तुम्हारे ही शहर की गलियों में घर के निशानें ढूंढ रही हूँ कभी रूह में तो कभी जिसमें भटक रही हूँ इस भटकन की अटकन अब तुम ही हो तुम्हें पाऊँ तो ही शायद पनाह मिले शायद... तुम तक जाने का रास्ता है जिसे मैं भटकन कह रही हूँ। -**बेन्नु सतीशकॉंत**

### आज का युवा, बाढ़ की मछली हो गया

आज का युवा, बाढ़ की मछली हो गया है जिसकी नियति भटकना है कभी वो पेट के लिए भटकता है तो कभी बहाव के सामने कमजोर होने से कुछ को इस भटकना में समंदर भी मिल जाते हैं पर अप्सोस ! बहुत भटकते ही रह जाते हैं क्योंकि, हर नदी-नाले की किस्मत में,

समंदर नही होता ! - **यू एस मिश्रा स्वनिल**



#### योगेश कुमार गोयल

विधानसभा चुनावों के मामले में खर्चीले चुनाव की बात करें तो कर्नाटक का पिछला विधानसभा चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खर्च किए गए धन के मामले में अब तक का देश में सबसे महंगा विधानसभा चुनाव रहा, जहां 9.5-10.5 हजार करोड़ रुपये खर्च लेने का अनुमान लगाया गया था, जो कर्नाटक के उससे पहले के चुनावी खर्च से दोगुना था। बलाकि चुनाव आयोग द्वारा प्रति उम्मीदवार अधिकतम 70 लाख रुपये खर्च की सीमा निर्धारित की जा चुकी है लेकिन सभी राजनीतिक दल अपनी ब्रांडिंग से लेकर विज्ञापन तक पर जिस प्रकार भारी-भरकम धनराशि खर्च करते हैं, उससे जाहिर है कि इस तरह के नियम सिर्फकागजों तक ही सीमित हैं और चुनाव आयोग भी इस तथ्य से अपरिचित नहीं है। दरअसल चुनाव आयोग के नियमानुसार लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है लेकिन राजनीतिक दलों के खर्च के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है।



### रमेश सर्गाफ

मध्यप्रदेश में कांग्रेस दो सीटें जीतने की स्थिति में है। वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर राज्यसभा में जाना चाहते हैं। इसके लिए कांग्रेस पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अरुण यादव, सुरेश पौरी, मीनाक्षी नटराजन जैसे दर्जनों नेता है जिनकी नजर राज्यसभा टिकट पर लगी हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस अपने दम पर एक सीट जीतने की स्थिति में है। वहां पूर्व केंद्रीय मंत्री मलिकार्जुन खड्गे, वीरप्पा मोइली, बीके हरिप्रसाद, सलीम अहमद जैसे नेताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। गुजरात की दो सीटों पर मधुसूदन मिश्री, दीपक बावरािया, शक्ति सिंह गोहिल, राजीव दुबाला, राज बब्बर प्रयास कर रहे हैं।

# साल दर साल महंगी होती चुनावी प्रक्रिया

#### चुनावों में धन-बल का बढ़ता इस्तेमाल

पिछले कुछ वर्षों से देशभर में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, कमोवेश सभी में न केवल अपराधिक छवि के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ रही है बल्कि चुनावों में धन-बल का बढ़ता इस्तेमाल भी चिंता का सबब बना है। इसी के मद्देनजर गत 13 फरवरी को उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीति में दागियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए चुनाव सुधारों को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। सर्वोच्च अदालत ने सभी राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर अपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों का विवरण डालने के अलावा यह हिदायत भी दी है कि वे यह भी बताएं कि ऐसे उम्मीदवारों को उन्होंने अपना प्रत्याशी क्यों बनाया, जिनके खिलाफ अपराधिक मामले लंबित हैं। अदालत ने यह आदेश सितम्बर 2018 में पांच जजों की संविधान पीठ के फैसले से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के आधार पर भाजपा नेता और बकील अध्वनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर दिए हैं। अदालत ने अपने उस फैसले में अपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में घोषणा करने के निर्देश दिए थे। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि चुनाव जीतने की संभावना ही अपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के चयन का एकमात्र कारण नहीं हो सकता और निर्देशों का अमल नहीं करने वाले राजनीतिक दलों पर अवमानना की कार्यवाही की जा सकती है। दरअसल अदालत और चुनाव आयोग की चिंता यह है कि उनके तमाम प्रयासों के बावजूद अपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार न केवल चुनाव दर चुनाव बड़ी संख्या में मैदान में उतर रहे हैं बल्कि चुनाव जीतकर सरकार में जगह भी बना रहे हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ चुनावों में संसद में दागी सांसदों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। 2004 में जहां संसद में पहुंचे 24 फीसदी सांसद दागी थे, वहीं

2009 में ऐसे सांसदों की संख्या बढ़कर 30 फीसदी, 2014 में 34 और 2019 में 43 फीसदी दर्ज की गई। पिछले दिनों हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अपराधिक छवि के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने के साथ चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए इस्तेमाल होने वाली अवैध सामग्री का मामला भी पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ता नजर आया। चुनाव



आयोग के मुताबिक पिछले चार विधानसभा चुनावों में गंभीर अपराधिक मामलों में फंसे उम्मीदवारों की हिस्सेदारी 2008 के विधानसभा चुनाव में चार फीसदी से बढ़कर इस बार के चुनाव में 15 फीसदी हो गई है। यही नहीं, पिछले चुनाव की तुलना में इस बार नकदी, शराब, नशीले पदार्थ तथा कीमती धातुओं की जब्ती में 25 फीसदी से भी अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। चुनाव में अवैध सामग्री की धरपकड़ संबंधी चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2015 के विधानसभा चुनाव में कुल 24279766 रुपये मूल्य की नकदी, अवैध शराब, नशीले पदार्थ तथा कीमती धातुएं जब्त की गई थी जबकि चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार के चुनाव में 52.87 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी, शराब, नशीले पदार्थ व कीमती धातुएं जब्त की गईं। इसमें 32.18 करोड़ का सोना, चांदी व अन्य

कीमती धातुएं, 10.02 करोड़ नकद, 5.87 करोड़ की ड्रस व अन्य नशीले पदार्थ तथा 2.67 करोड़ रुपये की तस्करी की शराब शामिल थी। चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी, कुकर, साड़ियां इत्यादि बांटने के मामले तो अक्सर सामने आते रहे हैं लेकिन दिल्ली के दंगल में पहली बार लैपटॉप बांटने के प्रयास भी खूब हुए। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार

चुनाव के दौरान 2.16 करोड़ रुपये मूल्य के लैपटॉप, साड़ी, कुकर इत्यादि जब्त किए गए। चुनावी शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिहाज से चुनावों में अपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या भी चिंताजनक है। चुनावी विश्लेषण से जुड़ी शोध संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के चुनाव मैदान में उतरे कुल 672 उम्मीदवारों में से हत्या, अपहरण, बलाकार, महिलाओं पर अत्याचार जैसे

गंभीर अपराधिक मामलों में फंसे प्रत्याशियों की संख्या 104 (15 प्रतिशत) थी जबकि 2015 में ऐसे प्रत्याशियों की संख्या 11 फीसदी, 2013 में 12 फीसदी और 2008 में 4 फीसदी थी। चुनावी मैदान में भाग्य आजमाने उतरे 133 उम्मीदवारों पर अपराधिक मामले चल रहे हैं जबकि पिछले

चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 114

चुनाव के दौरान 2.16 करोड़ रुपये मूल्य के लैपटॉप, साड़ी, कुकर इत्यादि जब्त किए गए। चुनावी शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिहाज से चुनावों में अपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या भी चिंताजनक है। चुनावी विश्लेषण से जुड़ी शोध संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के चुनाव मैदान में उतरे कुल 672 उम्मीदवारों में से हत्या, अपहरण, बलाकार, महिलाओं पर अत्याचार जैसे

गंभीर अपराधिक मामलों में फंसे प्रत्याशियों की संख्या 104 (15 प्रतिशत) थी जबकि 2015 में ऐसे प्रत्याशियों की संख्या 11 फीसदी, 2013 में 12 फीसदी और 2008 में 4 फीसदी थी। चुनावी मैदान में भाग्य आजमाने उतरे 133 उम्मीदवारों पर अपराधिक मामले चल रहे हैं जबकि पिछले

चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 114

चुनाव के दौरान 2.16 करोड़ रुपये मूल्य के लैपटॉप, साड़ी, कुकर इत्यादि जब्त किए गए। चुनावी शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिहाज से चुनावों में अपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या भी चिंताजनक है। चुनावी विश्लेषण से जुड़ी शोध संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के चुनाव मैदान में उतरे कुल 672 उम्मीदवारों में से हत्या, अपहरण, बलाकार, महिलाओं पर अत्याचार जैसे

गंभीर अपराधिक मामलों में फंसे प्रत्याशियों की संख्या 104 (15 प्रतिशत) थी जबकि 2015 में ऐसे प्रत्याशियों की संख्या 11 फीसदी, 2013 में 12 फीसदी और 2008 में 4 फीसदी थी। चुनावी मैदान में भाग्य आजमाने उतरे 133 उम्मीदवारों पर अपराधिक मामले चल रहे हैं जबकि पिछले

चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 114

# नये लोगों को आगे बढ़ाये कांग्रेस

दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी सकते की स्थिति में है। दिल्ली के सिंहासन पर वर्षों एक छत्र राज करने वाले कांग्रेस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दिल्ली में उसको इतनी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उसके तीन उम्मीदवार को छोड़कर बाकी सभी की जमातत तक जस हो जायेगी। पिछली बार की तरह इस बार भी दिल्ली में कांग्रेस अपना खाता खोलने में नाकाम रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर भी कांग्रेस नेता खुश नजर आ रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि आप की जीत हुई और धोखेबाज हार गये। दिल्ली के लोग जो कि भारत के सभी हिस्सों से ताल्लुक रखते हैं ने भाजपा के भ्रवीकरण, विभाजनकारी और खतरनाक एजेंडे को हरा दिया। मैं दिल्ली के लोगों को सेल्यूट करता हूं। जिन्होंने उन राशियों के लोगों के लिए एक उदाहरण पेश किया है जहां 2021 और 2022 में चुनाव होने वाले हैं।

पी चिदंबरम के इस ट्वीट पर दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष व पूर्व राष्ट्रपति ग्रेण्ड मुखर्जी की पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पी चिदंबरम की जमकर क्लास ली। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने उन पर निशाना साबते हुये दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को लेकर नेतृत्व पर भी सवाल उठाए हैं। मुखर्जी ने चिदंबरम के ट्वीट पर निशाना साधते हुए लिखा म कि क्या कांग्रेस ने भाजपा को हराने का काम क्षेत्रीय दलों को आउटसोर्स कर दिया है? यदि ऐसा नहीं है तो हम अपनी करारी हार की चिंता करने के स्थान पर आम आदमी पार्टी की जीत पर खुशी क्यों मना रहे हैं? और अगर इसका बयान हां में है, तो हमें अपनी (प्रदेश कांग्रेस समितियां) दुकान बंद कर देनी चाहिए। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा था कि शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने में देरी और एकजुटता की कमी के कारण यह शिकस्त हुई है।

दिल्ली महिला कांग्रेस की प्रमुख शर्मिष्ठा ने कहा था हम दिल्ली में फिर हार गए। आत्ममंथन बहुत हुआ अब कार्रवाई का समय है। उन्होंने सवाल किया कि अगर भाजपा विभाजनकारी राजनीति कर रही है। केजरीवाल स्मार्ट पॉलिटिक्स राजनीति कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? क्या



हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि हमने घर को व्यवस्थित रखने के लिए पूरा प्रयास किया? शर्मिष्ठा मुखर्जी के बयान के बाद कांग्रेस में कपिल सिब्बल जैसे सभी बयान वीर नेताओं को मो मानो सांप सूंघ गया हो। किसी ने भी मुखर्जी की बात काटने की हिम्मत नहीं दिखायी। उल्टे मिलींद देवड़ा, जयराम रमेश ने मुखर्जी के बयान का समर्थन ही किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद लगता है कि कांग्रेस के लिए 2020 की साल अच्छा नहीं रहेगा। इसी साल बिहार विधानसभा के भी चुनाव होने हैं जहां भाजपा जनाता दल (यू )का मजबूत गठबंधन सरकार में है। उसके मुकाबले बिहार में कांग्रेस कुछ खास कर पाएगी ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इसी वर्ष 73 राज्यसभा सीटों के चुनाव भी होने हैं। राज्यसभा सीटों के चुनाव में भी कांग्रेस को लाभ

होता नहीं दिख रहा है। राज्यसभा में फिलहाल कांग्रेस के पास 46 सीटें हैं। इस साल राज्यसभा में कांग्रेस की 17 सीटें खाली होगी उनमें से कांग्रेस 11 सीटें ही जीत पाएगी। इस तरह देखे तो कांग्रेस को राज्यसभा में 6 सीटों का नुकसान होने वाला है। हालांकि कांग्रेस को राजस्थान में दो, मध्यप्रदेश

में एक, छत्तीसगढ़ में दो व गुजरात में एक सीट का फायदा होगा। लेकिन उसे आंध्र प्रदेश में दो, अरुणाचल प्रदेश में एक, असम में एक, हिमाचल प्रदेश में एक, कर्नाटक में एक, उत्तर प्रदेश में एक, उत्तराखंड में एक, मेघालय में एक, मिजोरम में एक व ओडिशा में एक सीट का घाटा भी होगा।

इस वर्ष के राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा,अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दिल्ली, पुडुचेरी सहित 11 प्रदेशों में पूरी तरह साफनो जाएगी। राज्यसभा में कांग्रेस की स्थिति में है। जहां से पूर्व

मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पुत्र दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा में भेजना भेजना चाहते हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा की मौजूदा सदस्य कुमारी सैलेजा फिर से टिकट पाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी राज्यसभा में जाकर अपनी सुविधाएं बरकरार रखने का प्रयास कर रहे हैं।

## QUIZ TIME

- किस बैंक ने देश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए वाहकों को प्रोत्साहित करने के लिए 'बीन कार लोन' शुरू किया है? (कैनरा बैंक / स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया)
- चीन के चेंगदू में आयोजित 2019 विश्व पुलिस और फ़ायर गैम्स में कुश्ती (86 किग्रा वर्ग) में स्वर्ण पदक किसने जीता?
- किस देश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ऑर्डर-फ़र्ट

वलास से सम्मानित किया ?  
4) रिवंशा किस भाषा का शब्द है?  
(क) रूसी (ख) तुर्की (ग) पश्तो (घ) जापानी  
5) भारत का पहला ह्यूमनजीए पुलिस रोबोट का नाम बताए ?

Ramaquiz

## आज का इतिहास

**नई दिल्ली** । 1389 - सुलतान ग्यासुद्दीन तुगलक द्वितीय की दिल्ली में हत्या। 1630 - मराठ शासक शिवाजी का जुनेर में जन्म। 1719 - मुगल शासक फर्रुखसियार की हत्या । 1891 - अमृत बाजार पत्रिका का दैनिक प्रकाशन शुरू हुआ। 1895 - हिन्दी के जाने माने प्रकाशक मुंशी नवल किशोर का निधन । 1915 - स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले का निधन । 1942 - द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई शहर डाव्रिन पर जापानी लड़ाकू विमानों के हमले में 243 लोग मारे गए। 1960 ङ्ग चीन ने सफलतापूर्वक पहले ध्वनि रॉकेट टी -7 का परीक्षण किया। 1963 - सोवियत संघ ने अमेरिकी राष्ट्रपति जान एफ कैनेडी को क्यूबा से अपने कई हजारों सैनिक को हटाए जाने की सूचना दी। 1964 - फिल्म अभिनेत्री सोनू वालिया का जन्म हुआ।



## न्यूज गैलरी

### वुहान से भारतीयों को निकालने वाले एयर इंडिया कर्मियों की प्रशंसा

**नई दिल्ली ।** केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने के बाद चीन के वुहान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के अभियान में शामिल एयर इंडिया के 68 कर्मचारियों को आज प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया प्रशंसा पत्र सौंपा। नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल, एयर इंडिया के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राजीव बंसल, पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक अश्विनी लोहानी सहित मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। चीन में नोवेल कोरोना वायरस के प्रमुख केन्द्र वुहान शहर से कुल 647 भारतीयों और मालदीव के सात नागरिकों को निकाला गया था।

### ट्रेन टिकट बुकिंग पर फ्री कैसिलेशन सुरक्षा फ्री कैसिलेशन सुरक्षा

**नई दिल्ली ।** ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी कर्म्मटिकट ने फ्री कैसिलेशन सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की है जिसका उपयोग करने वाले ग्राहक ट्रेन के प्रस्थान से 4 घंटे पहले या चार्ट तैयार होने तक अपना ट्रेन टिकट रद्द कर सकते हैं। कंपनी ने मंगलवार को यहां जारी बयान में कहा कि यह सुविधा उसके ऑनलाइन प्लेटफर्म पर उपलब्ध करायी गयी है। इस विकल्प का चयन करने पर यूजर बिना किसी प्रश्न का जवाब दिए कैसिल किए हुए टिकट पर पुन रिफंड पाने के हकदार होंगे। तत्काल टिकट बुक करने वाले यूजर भी टिकट कैसिल करने पर पुन रिफंड का लाभ उठ सकते हैं, जबकि वर्तमान उपयोग करने में फ्री कैसिलेशन प्रोटोकशन लागू नहीं है। यदि पार्श्वल कैसिलेशन किया जाता है तो जिस यात्री का टिकट रद्द किया जायेगा उसका बेस रिकार्ड के बराबर राशि ही रिफंड होगी। अभी इस प्लेटफर्म पर 50 लाख से ज्यादा यूजर प्रतिदिन लगभग 30 हजार टिकट बुक कर रहे हैं।

### ओला ने चालकों को किया सम्मानित

**नई दिल्ली ।** वाजिब दामों पर टैक्सी सेवा उपलब्ध कराने वाली अग्रणी कंपनी ओला ने सात शहरों के अपने शीर्ष दर्जा प्राप्त चालकों को असाधारण सेवाओं के लिए ‘हीरोज ऑफ ओला’ प्रोग्राम के तहत सम्मानित किया है। कंपनी ने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में अपने चालकों की उनकी प्रतिबद्धता के लिए सराहना की और उन्हें उत्कृष्ट सेवा रिकार्ड के लिए पुरस्कृत किया। इस कार्यक्रम के हीरो रहे इन चालकों ने अपने परिवर्जनों के साथ सम्मान समारोह में हिस्सा । चालकों ओला के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाविश अग्वाली ने सराहना पत्र देकर सम्मानित किया। हीरोज ऑफ ओला कंपनी का एक सतत कार्यक्रम है जिसके तहत चालकों के प्रयासों की पहचान की गयी है जो अपने छोटे-बड़े कामों से ड्यूटी के दायरे से बाहर कार्य करके मिसाल कायम करते हैं।

# केरल में घरेलू पर्यटकों की संख्या में 16 प्रतिशत का इजाफा

**केरल पर्यटन के राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास फ़रीभूत हो रहे हैं और चालू वित्त वर्ष के पहले नौ माह (अप्रैल-दिसंबर -19) के दौरान घरेलू पर्यटकों की संख्या पहले की इसी अवधि के एक करोड़ 13 लाख की तुलना में 16 प्रतिशत बढ़कर एक करोड़ 32 लाख पर पहुंच गई।**

**नई दिल्ली ।**केरल के पर्यटन मंत्री कदकमपल्ली सुरेंद्रन ने मंगलवार को घरेलू विपणन अभियानों के पहले चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने और दूसरे चरण के प्रारंभ होने के संबंध में जानकारी देने के लिए

आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी । उन्होंने कहा कि राज्य में घरेलू पर्यटकों का मोह लगातार बढ़ रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और जोरदार वृद्धि हासिल होगी ।

श्री सुरेंद्रन ने बताया कि अभियान के दूसरे चरण के तहत देश के 10 शहरों में भागीदारी सम्मेलनों का आयोजन और प्रमुख पर्यटन व्यापार मेलों में भाग लेकर केरल के पारंपरिक कला रूपों तथा पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक उत्पादों के प्रति पर्यटकों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय



स्तर के भागीदारी सम्मेलनों के दूसरे चरण की शुरुआत जनवरी में की जा चुकी है और यह अगले माह तक जारी रहेगा। जनवरी में

यह सम्मेलन हैदराबाद, विशाखापत्तनम, कोलकाता और गुवाहाटी में आयोजित किए गए हैं जबकि इस माह अमृतसर और

चंडीगढ़ में सफल आयोजन के बाद दिल्ली में सम्मेलन आयोजित किया गया है। देश के गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर में 20 फरवरी, बेंगलुरु में तीन मार्च और चेन्नई में पांच मार्च को सम्मेलन आयोजित किए जायेंगे। श्री कदकमपल्ली ने बताया कि केरल ट्रेवल मार्ट के 11 वें संस्करण का प्रारंभ इस वर्ष 24 सितंबर से होगा। इसका आयोजन विलिंगडन द्वीप समूह के कोच्चि पोर्ट ट्रस्ट के सागर और समुद्रिका सभागृहों में 25 और 27 सितंबर को होगा। राज्य की पर्यटन सचिव रानी जार्ज ने कहा केरल में घरेलू पर्यटकों की

संख्या में बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि अभियान पर्यटकों को आकर्षित करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि देशभर से पर्यटक केरल में न केवल धरोहर के मामले में समृद्ध और मनोहर छत्र का अनुभव करने आते हैं बल्कि उन्हें विशेषकर विशु, त्रिशूरपरम और अन्य कई त्योहारों के आयोजन से सम्मान का भी अनुभव होता है । सुश्री जार्ज ने बताया अगले वर्ष 20 से 26 जनवरी तक तिरुवनंतपुरम के मध्य हरे-भरे कनकाक्कुट्टु पैलेस में सात दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव निशागांधी त्योहार का आयोजन होगा। इसके जरिये कला प्रेमियों

को देश के सर्वश्रेष्ठ और उभरती प्रतिभाओं के नजदीक आने का अवसर होगा। उत्सव के दौरान ओडिशी, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम , छत्र और कुचीपुडी जैसे नृत्यों का भव्य मंचन किया जायेगा। पर्यटन निदेशक पी बालाकिरण ने कहा कि राज्य में ऐसे नये और रोमांचक उत्पादों की श्रृंखला का समावेश किया गया है जो घरेलू पर्यटकों को भाते हैं और वर्ष में कभी भी आने के लिए आकर्षित करते हैं।

## मोदी ने 2024 तक भारत को 50 खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का रखा लक्ष्य

# ब्रिटेन को पीछे धकेल कर भारत बना विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था



**भारत में आर्थिक उदारीकरण का श्रीगणेश 1990 के दशक में शुरू हुआ और इसके बाद अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए आर्थिक सुधार की दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए जिनमें विदेशी व्यापार और निवेश पर नियंत्रण कम करना , उद्योगों पर नियंत्रण कम करना , सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण करना आदि शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत आत्मनिर्भर बनने की अपनी पहले की नीति से अब आगे बढ़ गया है और खुले बाजार वाली अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से सामने आया है । अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष(आईएमएफ) ने वर्ष 2018 के अंत में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 2019 में ब्रिटेन को पीछे धकेल कर भारत विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सफल होगा । आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा था ब्रिटेन के आर्थिक रुतबे में कमी आने की वजह विश्व उत्पादन में उभरते बाजारों की दर से बढ़ रही है ।**

भारत को 50 खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है और इस लिहाज से यह रिपोर्ट

भारत में आर्थिक उदारीकरण का श्रीगणेश 1990 के दशक में शुरू हुआ और इसके बाद अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए आर्थिक सुधार की दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए जिनमें विदेशी व्यापार और निवेश पर नियंत्रण कम करना , उद्योगों पर नियंत्रण कम करना , सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण करना आदि शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत आत्मनिर्भर बनने की अपनी पहले की नीति से अब आगे बढ़ गया है और खुले बाजार वाली अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से सामने आया है । अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष(आईएमएफ) ने वर्ष 2018 के अंत में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 2019 में ब्रिटेन को पीछे धकेल कर भारत विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सफल होगा । आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा था ब्रिटेन के आर्थिक रुतबे में कमी आने की वजह विश्व उत्पादन में उभरते बाजारों की दर से बढ़ रही है ।

### 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता दोगुनी होगी

**नई दिल्ली (वार्ता)।**सरकार देश में वर्ष 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता पांच करोड़ 35 लाख टन से बढ़ाकर दस करोड़ 80 लाख टन करेगी । दुधार पशुओं में आनुवांशिक सुधार के माध्यम तथा कुछ अन्य उपायों से दूध उत्पादन बढ़ाया जायेगा । पिछले पांच साल से देश में 6.4 प्रतिशत की दर से दूध उत्पादन बढ़ रहा है। यह उत्पादन वर्ष 2014-15 में 14 करोड़ 63 लाख टन से वर्ष 2018-19 में बढ़कर 18 करोड़ 77 लाख टन हो गया है । इसमें करीब 54 प्रतिशत का बाजार में उपयोग होता है जबकि 46 प्रतिशत का ग्रामीण या स्थानीय स्तर पर उपयोग होता है। व्यवसाय वाले दूध में संगठित क्षेत्र का हिस्सा 36 प्रतिशत है। पिछले दो साल के दौरान सहकारी क्षेत्र में दूध की खरीद नौ प्रतिशत की दर से बढ़ रही है ।

पशुपालन और डेयरी विभाग

## ओरिएंट ने कम बिजली खपत वाले आई-सीरीज पंखे उतारे

**री के विरला समूह की कंपनी ओरिएंट इलेक्ट्रिक लि.ने मंगलवार को आभी बिजली खपत वाले आई-सीरीज पंखे पेश किये हैं ।**

**नई दिल्ली ।**कंपनी ने दावा किया है कि ईसीएम टेक्नालॉजी युक्त ये पंखे सामान्य पंखों की तुलना में काफी कम बिजली खपत करते हैं। एक पंखा का इस्तेमाल करने में जितनी कम बिजली कम खर्च होती है उससे 1500 रुपये तक बचत हो सकती है। नयी रेंज में आई-फ्लोरल, हेक्टर 500 और आईओटी इनेबल्ड तथा ध्वनि नियंत्रित आई-फ्लोट फैन शामिल है जो विभिन्न रंगों और डिजाइन में उपभोक्ताओं को उपलब्ध होंगे। ये

पंखे बीईई-5 रेटिंग वाले हैं।

ओरिएंट इलेक्ट्रिक लि. के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश खन्ना ने इस मौके पर कहा कि कंपनी



की यह पेशकश बिजली की बचत करने वाले पंखों के वर्ग में अग्रणी होकर उभरने और साथ ही प्रीमियम पंखों के वर्ग में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लक्ष्य का एक मजबूत कदम है। उन्होंने

कहा कि कंपनी हमेशा ऐसा उत्पादों के विकास पर केन्द्रित रहती है जो नवोन्मेषी होने के साथ उत्कृष्ट हो। जलवायु से संबंधित स्थितियों से निपटने और पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ता के इस काल में ऊर्जा बचत पर सरकार के लगातार प्रयासों के मद्देनजर यह कंपनी की एक महत्वपूर्ण पहल है। इनवर्टर मोटर से लैस आई-सीरीज पंखों की यह रेंज स्मार्ट, ऊर्जा कुशल, आईओटी

इनेबल्ड और पर्यावरण अनुकूल है। आई-सीरीज रेंज किफायती मूल्य में विश्व स्तरीय टेक्नालॉजी प्रदान करके कंपनी का यह बड़ा कदम है।

### टीटीके प्रेस्टीज ने लांच किया वेट ग्राइंडर

**नई दिल्ली ।**रसोई उपकरण बनाने वाली कंपनी टीटीके प्रेस्टीज ने नया वेट ग्राइंडर लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को यहां जारी बयान में कहा कि यह दो मॉडल पीडब्ल्यूजी 07 और पीडब्ल्यूजी 08 में उपलब्ध है। यह ग्राइंडर उच्च गुणवत्ता के पत्थरों से लैस है, जिससे एक स्टेनलेस स्टील ड्रम है। दोनों मॉडल विभिन्न प्रकार के रंगों में उपलब्ध हैं। उसने कहा कि डोसा, रोटियां, इडली, नान, पूरियां, पराठे सभी आहारों का एक अभिन्न अंग हैं। इसकी को ध्यान में रखते हुये लोगों को बेटर और डॉ ब्राइंडर को डिजाइन किया गया है। वेट ग्राइंडर पीडब्ल्यूजी 07 की कीमत 4690 रुपये जबकि पीडब्ल्यूजी 08 मॉडल की कीमत 4695 रुपये है।

## सेफजॉब की नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के साथ भागीदारी

**नई दिल्ली ।** नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर ‘धांसू वुमन’ अभियान के लिए सेफजॉब ने भागीदारी की है। सेफजुकेट की प्रशिक्षण, कोशल और परामर्श इकाई सेफजॉब ने मंगलवार को यहां जारी बयान में कहा कि नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के साथ मिलकर जारी हुआ यह अभियान आगामी धांसू वुमन थीम संगीत पर केंद्रित है और सभी उम्र, वर्ग और जीवन के हर क्षेत्र की महिलाओं के अभियान में शामिल होने और इसका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता है।

उसने कहा कि इसमें 30 सबसे सफल महिलाओं की



कहानियां होगी जिसमें उद्यमी, वैज्ञानिक, शिक्षक, वकील, या एन्क्विस्ट, ऐसी महिलाएं जो इस दुनिया को बेहतर बनाने, सोहादपूर्ण स्थान बनाने के लिए अनथक काम करने वाली महिलाओं की कहानियां होंगी। सेफजुकेट की संस्थापक एवं

मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिव्या जैन ने कहा कि नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के साथ भागीदारी करके बहुत खुश हैं क्योंकि हम उन विभिन्न धांसू महिलाओं को पहचानने और उन्हें दुनिया के सामने लाने के लिए काम कर रहे हैं जिन्होंने अपने चुनिंदा कार्यक्षेत्रों में असाधारण प्रभाव डाला है। इन 30 महिलाओं के चयन की प्रक्रिया शुरू की गयी है, उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया की उन महिलाओं और उन सभी चीजों को सेलिब्रेट करने का दिन है जिनमें हम अपने समाजों में व्यापक बदलाव लाने के लिए खड़े हुए और लड़ाई लड़ी है।

### प्रथम पृष्ठ का शेष

#### पारम्परिक बजट निर्माण प्रक्रिया

से अलग हटकर वैकल्पिक व्यवस्थाओं और नवाचारी विचारों पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रोजगार पैदा करने वाली आर्थिक गतिविधियों पर लगातार ध्यान देना जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश जैसे राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है लेकिन उनके आधार पर आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने के प्रयासों में कमी दिखती है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की कृषि को अत्याधुनिक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कृषि से संबंधित अन्य आर्थिक गतिविधियों में विस्तार हो। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि उत्पादन में आगे है लेकिन इन उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच बनाने में कई बाधाएँ हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई देशों की बजट व्यवस्थाएँ वित्तीय जवाबदारी एवं बजट प्रबंधन जैसे कानूनों के बिना भी अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि इस बार के केन्द्रीय बजट में मध्यप्रदेश के हिस्से की 14 हजार करोड़ रूपए की राशि

की कमी है। उन्होंने बजट संसाधनों के प्रबंधन के लिए नई दृष्टि और नई सोच के साथ आगे बढ़ने और शासन में सुधार लाने पर जोर दिया। अहलूवालिया ने कहा कि परियोजनाएँ बनाएँ, उनके लिये बजट प्रावधान करना और समय रहते उन्हें उपलब्ध संसाधनों में पूरा करना पूरे विश्व में एक मान्य प्रक्रिया है। यह भी तथ्य है कि सरकारों के वित्तीय संसाधन सीमित हैं लेकिन परियोजनाएँ महत्वाकांक्षी हैं। सरकारों के पास सिर्फ आर्थिक अधोसंरचना परियोजनाओं के अलावा भी सामाजिक जिम्मेदारियों के कई काम और भी हैं। फलस्वरूप योजनाओं और परियोजनाओं की गति धीमी होकर ये पिछड़ने लगती हैं। निजी क्षेत्र किसी भी प्रकार का खतरा उठाने से बचता है जबकि सरकार हानि-लाभ से परे जन-कल्याण के उद्देश्य के लिए समर्पित होती है। दोनों क्षेत्रों की अपनी सीमाएँ हैं। इसलिए दोनों क्षेत्रों के परस्पर

सहयोग से काम करने के लिए एक उचित कानून की जरूरत नजर आती है। इस स्थिति से निपटने में वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून पूरी तरह से मददगार साबित नहीं हो पा रहा है। अहलूवालिया ने कहा कि बड़ी आर्थिक अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए और से गारंटी उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर भी विचार किया जाना चाहिए। सरकार को परियोजनाओं के लिए वित्तीय खतरा उठाने के प्रबंधन में सहयोगी मित्र की भूमिका निभाने पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए जो आर्थिक महत्व की अधोसंरचनात्मक परियोजना प्रस्तावित हो, उनमें गारंटी प्राथमिकता के साथ दी जाना चाहिए। इनमें सिंचाई और जल संचरणा निर्माण जैसी परियोजनाएँ शामिल हो सकती हैं।

#### आतंक पर पैंतरे फेल, पाक

एफएटीएफ पाकिस्तानी सबूतों से संतुष्ट नहीं हुआ तो उसे आखिर में ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से

बाहर निकालने में तुर्की और मलेशिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी पर नाकाम रहे।हालांकि पाकिस्तानी मीडिया एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट पर भरोसा कर रहा है। दक्षिण एशियाई मामलों के स्कॉलर माइकल कुगलमन ने कहा है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर तो नहीं निकल सकता, हां ये हो सकता है कि उसे ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाए। तब भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सोमवार को एफएटीएफ की बैठक शुरू हो गई है। बुधवार यानी 19 फरवरी से प्लेनरी की मीटिंग है जो पाकिस्तान के जवाब पर गौर करेगी। कुगलमन कहते हैं, पाकिस्तान के लिए इतनी जल्दी ग्रे लिस्ट से निकलना तो मुश्किल है। ये शायद इस साल के अंत में होने वाली बैठक में हो सकता है। हालांकि इसके लिए इमरान खान सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे।

#### पाक की नापाक कोशिशों

भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना की ओर से उसे मुहताड़ जवाब दिया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल डिल्लन ने

भरोसा जताया कि पाकिस्तान घाटी में शांति भंग करने की अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाएगा।

#### अर्थव्यवस्था टॉप -3 में

अब भारत में निवेश करना चाहती हैं और एफडीआई रिफॉर्ड भी देखा जाए तो साफ हो जाएगा कि आज तक का सबसे ज्यादा फॉरक्स रिजर्व्स भारत में हैं। देश की विकास दर को बेहतर बताते हुए कहा कि अगले साल तक देश की विकास दर 6 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। उनका कहना है कि आईएमएफ और आरबीआई ने भी इसके संकेत दिए हैं।

#### भारत दुनिया का 5वीं बड़ी

आकलन किस आधार पर किया है। पिछले साल के आंकड़े भी नहीं बताए। अपने आंकड़ों की बजाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ( आईएमएफ ) के डेटा दिए गए। 2011 में शुरू हुई यह वेबसाइट प्रमुख रूप से जनसंख्या के आंकड़ों के बारे में बताती है। वेबसाइट पर दावा किया गया है कि वह एक स्वतंत्र संस्था है। किसी राजनीतिक संस्था से उसका संबंध नहीं है।

## 25 साल पूरे होने पर एचडीएफसी बैंक 25 लाख पेड़ लगाएगा

**मुंबई।**25 साल पूरे होने के अवसर पर एचडीएफसी बैंक देश में 25 लाख पेड़ लगाएगा और 2500 सरकारी स्कूलों के क्लास रूमस डिजिटिज्ड करेगा। यह कार्यक्रम परिवर्तन के तहत किया जाएगा तथा अगले दो सालों में पूरा होगा। परिवर्तन बैंक के सामाजिक परिवर्तन अभियानों के लिए बैंक का एक मुख्य प्रयास है, जिसमें पर्यावरण, सामाजिक एवं प्रशासन के क्षेत्रों में काम किया जाता है। मुंबई में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मुनिसिपल स्कूल में आयोजित एक समारोह में श्री आदित्य पुरी, एमडी, एचडीएफसी बैंक ने 25 लाख पौधों से से प्रथम अमरुद का पौधा लगाया। श्री पुरी ने स्कूल में एक डिजिटल क्लास रूम का उद्घाटन भी किया। यह स्कूल बैंक द्वारा मुंबई में चुने गए 150 स्कूलों



में से एक है। स्वच्छ पर्यावरण एवं स्मार्ट क्लासरूम्स का कोई विकल्प नहीं। यदि हम अपने देश को दुनिया का एक प्रबल देश बनाना चाहते हैं, तो ये दोनों अत्यधिक आवश्यक हैं। हमने अपने अस्तित्व के 25 साल पूरे कर लिए हैं इसलिए हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम समाज की वापस देने के लिए अपना प्रयास करें। हमारी ओर से अपने देश को दिया गया यह छोटा सा योगदान है।

पादपर्ण किया था। ऑलरॉउंडर  
 डैरिल मिशेल को भी टीम में  
 वापसी हुयी है। उन्होंने अपना  
 एकमात्र टेस्ट नंबर में इंग्लैंड के  
 खिलाफ हैमिल्टन में खेला था।  
 टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की  
 टीम इस प्रकार है-केन  
 विलियमसन (कप्तान), टॉम  
 ब्लैंडेल, ट्रेट बोल्ड, कॉलिन डी  
 ग्रैंडहोम, काइल जैमिसन, टॉम  
 लाथम, डैरिल मिशेल, हैनरी  
 निकोस, एजाज पटेल, टिम  
 साऊदी, रॉस टेलन, नील वागनर,  
 बीजे वाटलिंग।

कब्जा कर लेने हेतु, राम बैगा निवासी चोपा ने एकवर्ती कनेक्शन में 1800 रुपये बिल आने की शिकायत की। पछेला निवासी राजेन्द्र वर्मा ने आवेदन देकर बताया कि दिनांक 17 दिसम्बर 2019 सीपी नम्बर 5850 के अनुसार लोकायुक्त भीषल के जाओड 238/2016-संपत्तिका शाखा के फाईल क्रमांक 08/2016 एवं संलग्न विभागीय जॉर्ज प्रकरण 01/2019 के सम्पूर्ण फाईल की नकल की मांग की कती बताया कि उक्त नकल हेतु मैं कई बार आवेदन दिया। परन्तु नकल नहीं दी जा रही है, उनके आवेदन को नकल शाखा की ओर त्वरित कार्यवाही हेतु भेजा गया। इसी तरह अन्य आवेदकों ने भी अपनी-अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए जिनके निराकरण हेतु संबंधित विभागों की ओर अग्रेषित किया गया।

